गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 278
दि. 09.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की समयसीमा तय होने से राजनीति गरमाई

जीएनएस)। रायपुर की सियासत उस वक्त अचानक तेज हो गई, जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की स्पष्ट समयसीमा घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। यह बयान केवल एक प्रशासनिक लक्ष्य नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की उस रणनीति का संकेत है, जिसमें नक्सल समस्या को अब निर्णायक मोड़ तक ले जाने का इरादा साफ झलकता है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद जहां भाजपा इसे अपनी उपलब्धियों और भविष्य की प्रतिबद्धता के रूप में पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए तीखा पलटवार किया है।

तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए अमित शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा बैठक में सुरक्षा बलों और प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अपनाई गई रणनीति के कारण नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी यह संदेश दिया कि सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी, सड़क, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आधारभूत ढांचे के विस्तार, नक्सल फंडिंग नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई और प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के चलते अब निर्णायक सफलता का समय आ गया है। शाह ने यह भी कहा कि कभी नक्सल हिंसा का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में अब विकास की नई तस्वीर उभर रही है और भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य को एक नई दिशा दी है।

अमित शाह ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया कि नक्सलवाद को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे विकास और विचारधारा दोनों के स्तर पर चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद कोई सामाजिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक भ्रामक और हिंसक विचारधारा है, जिसे लंबे समय तक कुछ राजनीतिक ताकतों से अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता रहा। शाह के मुताबिक, भाजपा सरकार ने इस सोच को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है और अब उसका परिणाम भी दिखने लगा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में 30 गुना वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय 17 गुना तक बढ़ी है, जो यह साबित करता है कि शांति और विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

इसके बाद 'ऑर्गेनाइजर' द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव "छत्तीसगढ़ 25: शिफ्टिंग द लेंस" में बोलते हुए अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को केवल राज्य या देश तक सीमित न बताते हुए इसे वैश्विक संदर्भ से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो इसका असर वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा पर भी पड़ता है। उनके अनुसार, किसी भी राष्ट्र या राज्य की बुनियाद सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि पर टिकी होती है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

हालांकि, अमित शाह के इन दावों और आरोपों ने राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया। कांग्रेस ने उनके बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ा विरोध जताया। पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में माओवाद पर प्रभावी अंकुश लगाया गया था और कई इलाकों में शांति स्थापित हुई थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि झीरम घाटी जैसी दर्दनाक घटना भाजपा शासन के दौरान हुई थी, जिसे नक्सल हिंसा के सबसे बड़े उदाहरणों में गिना जाता है। डहरिया का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों को रोजगार, शिक्षा और जल-जंगल-जमीन के अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए थे।

कांग्रेस नेताओं का यह भी तर्क है कि नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या को केवल सख्त बयानों और समयसीमा तय करने से खत्म नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, इसके लिए स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना, आदिवासी समाज की समस्याओं को समझना और विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार नक्सलवाद के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई कहीं अधिक जटिल है।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने नक्सलवाद के खिलाफ कभी ठोस और दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान नक्सलियों के हौसले बढ़े और समस्या के समाधान के बजाय केवल बयानबाजी की गई। उनके मुताबिक, भाजपा सरकार ने केंद्र और राज्य के समन्वय से सुरक्षा बलों को मजबूत किया, खुफिया तंत्र को बेहतर बनाया और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति दी, जिसका असर अब साफ दिख रहा है।

अमित शाह ने अपने संबोधन में नक्सलियों को भी सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती और जो लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। विशेष रूप से महिला नक्सलियों से उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे हथियार छोड़ें और सम्मानजनक जीवन की ओर लौटें, सरकार उन्हें सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह अपील एक ओर जहां सख्त कार्रवाई के साथ मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है, वहीं यह भी संकेत देती है कि सरकार अब नक्सलवाद के अंतिम चरण की तैयारी में है।

गृह मंत्री ने बस्तर को लेकर एक बड़ा विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि यदि नक्सलवाद न होता, तो बस्तर आज देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में गिना जाता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले दस वर्षों में बस्तर को देश का रोल मॉडल जिला बनाया जाएगा, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन के नए अवसर पैदा होंगे। 9 फरवरी को अमित शाह के बस्तर दौरे और 'बस्तर पंडुम-2026' के समापन कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा को भी इसी बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नक्सलवाद के मुद्दे पर यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि छत्तीसगढ़ अब केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श के केंद्र में भी है। अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का ऐलान सरकार की मंशा और आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह एक बड़ी चुनौती भी है। यदि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करती है, तो यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। वहीं, यदि तय समयसीमा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के रूप में भुनाने की कोशिश करेगा।

कुल मिलाकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अमित शाह के सख्त ऐलान ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा इसे निर्णायक लड़ाई का ऐलान बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बयान करार दे रही है। आने वाले महीनों में जमीनी हालात, सुरक्षा अभियानों की दिशा और विकास कार्यों की रफ्तार यह तय करेगी कि यह समयसीमा केवल एक घोषणा बनकर रह जाती है या वास्तव में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के अंधेरे से बाहर निकलकर शांति और विकास के नए दौर में प्रवेश करता है।

एक साल की सरकार पर सियासी संग्राम, 'फ्रॉड डे' कहकर AAP का भाजपा पर तीखा प्रहार

जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर सियासत पूरी तरह गरमा गई है। जहां भाजपा इसे विकास, स्थिरता और सुशासन का वर्ष बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इस दिन को 'फ्रॉड डे' करार देते हुए सरकार पर गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं। राजधानी की राजनीति में यह टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया, प्रशासनिक फैसलों और हालिया हादसों तक फैल गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक साल पहले इसी दिन दिल्ली में ऐसी सरकार बनी, जिसकी नींव झूठ, फर्जीवाड़े और चुनावी अनियमितताओं पर रखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा और जनता को गुमराह करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया। उनके अनुसार, भाजपा जिस जश्न को मना रही है, वह असल में लोकतंत्र के साथ हुए धोखे की सालगिरह है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनुचित साधनों का

इस्तेमाल किया गया। उन्होंने प्रवेश वर्मा से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारिवारिक नाम, संस्थाओं और संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग हुआ, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, यह केवल एक सीट या एक नेता का मामला नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है।

AAP नेता ने दिल्ली को 'फर्जीवाड़े की प्रयोगशाला' बताते हुए कहा कि गलत तरीकों से सरकार बनाने की शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने कांग्रेस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों में कथित चुनावी गड़बड़ियों पर राजनीतिक दलों का रुख अलग-अलग रहता है। उनके अनुसार, अगर किसी राज्य में लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं, तो उसे केवल राजनीतिक सुविधा के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली, पश्चिम बंगाल या कोई भी राज्य—सभी देश का हिस्सा हैं और हर जगह समान मानदंड लागू होने चाहिए।

वोटों में कमी और कथित सामान वितरण का मुद्दा भी AAP के हमले का बड़ा आधार रहा। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में करीब 42 हजार वोट कम हो गए, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए जूते, चप्पल और अन्य सामान बांटे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर 'फर्जीवाड़ा दिवस की शुभकामनाएं' लिखकर तंज कसा, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। AAP का हमला केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। सौरभ भारद्वाज ने जनकपुरी हादसे को लेकर भी दिल्ली सरकार और प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले कमल ध्यानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सामने आ जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस देरी के पीछे क्या वजह है और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्य ठेकेदार KK Spun को बचाया जा रहा है और उसका नाम जानबूझकर जांच से दूर रखा गया है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, शुरुआत से ही सरकार और संबंधित मंत्री मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री आशीष सूद और प्रवेश वर्मा ने बैरिकेडिंग को लेकर गलत बयान दिए, जबकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट रूप से बैरिकेडिंग न होने का जिक्र है। उनके अनुसार, यह सीधे तौर पर जनता को गुमराह करने का प्रयास है।

AAP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिस थानों में पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं की गईं और पुलिस पर ऊपर से दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि असली दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मजदूरों और निचले स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि बड़े नामों और जिम्मेदार लोगों को बचाया जा सके। उनके मुताबिक, यदि सरकार सच में जवाबदेह है, तो उसे मंत्रियों और अधिकारियों के बयानों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।

ईरान की मिसाइल 'रेड लाइन' पर इजराइल का सख्त अलर्ट, अकेले हमले का ऐलान

जीएनएस)। तेल अवीव और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीतिक और सैन्य चर्चाओं के बीच इजराइल ने अमेरिका को एक बेहद स्पष्ट और कठोर संदेश दे दिया है। इजराइल का कहना है कि यदि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर तय की गई 'रेड लाइन' पार की, तो वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय समर्थन या संयुक्त कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना अकेले ही सैन्य हमला करेगा। इजराइली रक्षा प्रतिष्ठान के मुताबिक, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अब केवल एक क्षेत्रीय खतरा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर इजराइल के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है।

सूत्रों के अनुसार, बीते कुछ हफ्तों में इजराइल और अमेरिका के बीच कई उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं, जिनमें रक्षा, खुफिया और रणनीतिक मामलों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इन बैठकों के दौरान इजराइल ने अमेरिका को साफ तौर पर अवगत कराया कि वह ईरान की मिसाइल क्षमता, उसके उत्पादन नेटवर्क और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइली अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि हालात बिगड़ते हैं, तो मिसाइल निर्माण केंद्रों, परीक्षण स्थलों और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर एक साथ और व्यापक हमले किए जा सकते हैं, ताकि पूरे

कार्यक्रम को जड़ से कमजोर किया जा सके।

इजराइल की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है, जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा युद्ध, लेबनान सीमा पर हिज़्बुल्लाह की गतिविधियां और यमन में हूती विद्रोहियों के हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इजराइली सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन सभी मोर्चों के पीछे ईरान की रणनीतिक भूमिका है और उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम इस पूरी रणनीति की रीढ़ माना जा रहा है। एक इजराइली सुरक्षा सूत्र ने कहा कि अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। यदि ईरान तय सीमा से आगे बढ़ता है, तो इजराइल स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगा। हालांकि, इस सूत्र ने यह भी जोड़ा कि फिलहाल ईरान उस अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचा है, जिसे इजराइल ने 'रेड लाइन' के रूप में परिभाषित किया है। इसके बावजूद इजराइल ईरान के भीतर हो रहे हर सैन्य, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास पर चौबीसों घंटे नजर रखे हुए है।

इजराइली नेतृत्व बार-बार यह दोहराता रहा है कि उसका देश अपनी रक्षा के लिए अकेले कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ईरान को ऐसे रणनीतिक हथियार विकसित करने या दोबारा खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो भविष्य में इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हों। उनका मानना है कि यदि समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो बाद में इसकी कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, हालिया चर्चाओं में इजराइल ने अमेरिका के सामने मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े अतिरिक्त ठिकानों की सूची और उन पर संभावित हमलों की रूपरेखा भी रखी है। इजराइली सैन्य नेतृत्व को इस बात की गहरी चिंता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ केवल सीमित सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुन सकता है, जैसा उसने हाल के महीनों में यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ किया था। इजराइल का मानना है कि इस तरह की सीमित कार्रवाई ईरान की असली सैन्य क्षमता को खत्म करने में नाकाम रहेगी।

एक वरिष्ठ इजराइली सैन्य अधिकारी ने आशंका जताई कि यदि कुछ ठिकानों पर हमले के बाद ही 'सफलता' का ऐलान कर दिया गया, तो इसके दीर्घकालिक परिणामों से निपटने की जिम्मेदारी अंततः इजराइल पर ही आ जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, ईरान की रणनीति अक्सर धैर्य और दीर्घकालिक तैयारी पर आधारित होती है, और वह अस्थायी नुकसान के बाद अपने कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने में सक्षम है। ऐसे में आधे-अधूरे कदम समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे और जटिल बना सकते हैं।

इसी बीच यह भी संकेत मिले हैं कि इजराइल वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ओमर टिशलर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान सैन्य समन्वय, खुफिया साझा करने और संभावित परिदृश्यों पर गहन चर्चा होगी। इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अमेरिका उसकी चिंताओं को गंभीरता से ले और किसी भी फैसले से पहले क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक प्रभावों पर विचार करे।

दरभंगा कांड से उभरे सवाल, बिहार की कानून व्यवस्था फिर कटघरे में

जीएनएस)। पटना। दरभंगा में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गई, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था, शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना बन गई है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें न कानून का डर है और न ही प्रशासन का।

तेजस्वी यादव ने दरभंगा की इस घटना को अमानवीय, शर्मनाक और सभ्य समाज को कलंकित करने वाली बताया। उन्होंने कहा कि एक छह साल की बच्ची, जो अभी दुनिया को समझना भी शुरू नहीं कर पाई थी, उसके साथ दरिंदगी कर उसकी जान ले ली गई। यह घटना बताती है कि राज्य में सबसे कमजोर वर्ग—महिलाएं, बच्चियां और गरीब—खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में पीड़ितों की सुनवाई लगभग खत्म हो चुकी है और अपराध के बाद भी न्याय की प्रक्रिया इतनी कमजोर है कि लोगों का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है।

तेजस्वी यादव का कहना है कि यह कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि बीते कुछ समय में ऐसी घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला सामने आई है, जो यह दिखाती है कि बिहार में कानून व्यवस्था गंभीर संकट में है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और सार्वजनिक बयानों में राज्य में हुई कई आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार को घेरा। उनके मुताबिक, पुलिस की कार्यशैली, कम दोषसिद्धि दर और गंभीर अपराधों पर शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने

अपराधियों को खुली छूट दे दी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं करती, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है और जांच प्रक्रिया को जानबूझकर कमजोर किया जाता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अपराधियों और सत्ता के कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच कथित सांठगांठ के कारण ही कई मामलों में दोषियों को संरक्षण मिलता है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं।

तेजस्वी यादव ने खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और एसिड अटैक जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इन पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब राज्य का मुखिया ही संवेदनशील मुद्दों पर मौन साध ले, तो प्रशासनिक मशीनरी का मनोबल भी गिरता है।

तेजस्वी यादव ने हालिया घटनाओं की एक लंबी सूची गिनाते हुए कहा कि पटना में एक नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, मधेपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, खगड़िया में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या, मुजफ्फरपुर में महिला के अपहरण के बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर, सुपौल, मोतिहारी और कटिहार में महिलाओं की हत्याएं, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, मोतिहारी में युवती पर एसिड अटैक और छपरा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा घटनाएं होना यह दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं बचा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षण के कारण बलात्कारियों और हत्यारों के हौसले बढ़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मंत्री और सत्ताधारी दल के नेता खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जो सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी उठाया कि जब इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, तब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापन और प्रचार में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद डरावनी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि एक बच्ची की जान जाने के बाद भी अगर सिस्टम नहीं जागता, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सरकार सख्त संदेश दे और दोषियों के खिलाफ त्वरित व कड़ी कार्रवाई करे, तो अपराधियों में डर पैदा हो सकता है। लेकिन जब कार्रवाई में देरी होती है, बयान अस्पष्ट होते हैं और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तो अपराधियों को यह संदेश जाता है कि वे बच सकते हैं।

तेजस्वी यादव ने मांग की कि दरभंगा मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई हो, दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए।

इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को नियंत्रण में होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दावों से आम लोगों का डर कम हो पाएगा। दरभंगा की मासूम बच्ची की मौत ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिहार में महिलाएं और बच्चे वाकई सुरक्षित हैं, या फिर कानून व्यवस्था सिर्फ फाइलों और बयानों तक ही सीमित रह गई है।

संपादकीय

गुमशुदाओं की तलाश और मिलने की आस

पिछले दिनों इस खबर ने दिल्ली और देश के लोगों को चौंकाया कि इस साल जनवरी माह में ही देश की राजधानी में 800 लोग लापता पाए गए, जिसमें महिला, बच्चे व अन्य वयस्क भी शामिल हैं। जैसा कि स्वाभाविक था दिल्ली में लापता लोगों का आंकड़ा सामने आने के बाद आम लोगों में चिंता व्याप्त हो गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इस समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान गया। बेलगाम सोशल मीडिया पर तो इन आंकड़ों पर अपनी-अपनी सुविधा और राजनीतिक हितों के मद्देनजर व्याख्या और बयानबाजी सामने आने लगी। पब्लिक फोरम पर कहा जाने लगा कि यह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद घर से निकलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर तमाम तरह की सलाहें दी जाने लगीं। कुछ लोग देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोगों में भय से जुड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन इस बाबत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़े भी अधिक चिंता बढ़ाने वाले नजर आए। प्रथम दृष्टया यह खबर परेशान करने वाली है, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि यह स्थिति पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्थिति की पुनरावृत्ति ही है। लेकिन यदि बीते कुछ सालों में लापता होने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इस साल जनवरी में सामने आई लापता लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। इस बाबत दिल्ली पुलिस का कहना है कि जनवरी 26 में कुल 1,777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम दृष्टया यह संख्या भले ही बढ़ी लगे, लेकिन जब पिछले दो सालों के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाती है तो नई तस्वीर उभरती है। दरअसल, इन आंकड़ों की तह में जाएं तो दिल्ली का विशाल इलाका व सघन जनसंख्या घनत्व भी इसके मूल में है।

दरअसल, एक बड़ी आबादी रोजगार व अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आती-जाती रहती है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में करीब 24,893 लोग लापता हुए थे। यानी एक माह में औसतन 2,074 लोग। वहीं साल 2025 में ये संख्या 24,508 लोग लापता हुए। अर्थात् हर माह 2,042 लोग गुम हुए। इस दृष्टि से जनवरी, 26 का आंकड़ा इस संख्या से कम है। सवाल है कि 2026 के पहले माह के आंकड़ों को लेकर भय क्यों व्याप्त हुआ? दरअसल, पहले पंद्रह दिनों के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में हर रोज 54 लोग लापता हो रहे थे। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों ने इसके मूल में किसी संकट को देखा। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये आंकड़े स्थायी गुमशुदगी के नहीं होते। कुछ लोग अल्पकाल के लिए कहीं चले जाते हैं और देर रात तक घर भी लौट आते हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन और ऐप आधारित सिस्टम के जरिये लोग जल्दबाजी में अपने परिजनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मसलन यदि कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल से लौटने में देर कर दे, कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक फोन संपर्क से कट जाए या कोई बुजुर्ग भटकने पर देर से घर पहुंचे तो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये कथित गुमशुदा लोग कुछ समय बाद घर तो लौट आते हैं, लेकिन लोग पुलिस डेटा को अपडेट नहीं करते। फलस्वरूप पुलिस आंकड़ों में उनकी गुमशुदगी बनी रहती है। पुलिस का दावा है कि लापता लोगों को खोजने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। साल 2016 में जो 23,409 लोग लापता हुए थे, उनमें से करीब 85 फीसदी नौ साल के भीतर मिल गए। साल 2025 में दर्ज मामलों में 63 फीसदी लोगों को भी एक साल के भीतर तलाश लिया गया। दलील है कि कई जटिल मामलों में तलाश का काम एक साल तक पूरा नहीं हो पाता। अन्य राज्यों में उनकी तलाश में समय लगता है। फिर भी पुलिस का दावा है कि दिल्ली के लापता लोगों की संख्या का आंकड़ा दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है।

स्वच्छ भारत मिशन को रफ़्तार देते इलेक्ट्रिक वाहन

> शहरों में कचरा ढुलाई में लगे डीजल-पेट्रोल व सीएनजी वाहनों की जगह विभिन्न चरणों में ई-वाहनों को लाना चाहिये। एक शोध के मुताबिक, इससे कचरा संग्रहण की घटती है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव और व्यापक हो सकते हैं। पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाएं इसमें मददगार होंगी।

बीते कुछ वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन से शहरी स्वच्छता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। देश के लगभग सभी शहरों में घरों के दरवाजे से कचरे का संग्रहण (डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन) अब एक सामान्य और नियमित व्यवस्था बन चुकी है। दूसरी तरफ, 'फेम' और हालिया घोषित 'पीएम ई-ड्राइव' जैसी योजनाएं भारत के 'क्लीन मोबिलिटी' के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही हैं। कचरा संग्रहण वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन (पेट्रोल/ डीजल/ सीएनजी वाहनों की जगह इ-वाहनों का उपयोग) से, ये दोनों प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताएं परस्पर जुड़ सकती हैं। इससे कचरा संग्रहण वाहनों की परिचालन लागत घट सकती है व इन प्रदूषण-मुक्त वाहनों से स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव और व्यापक बनाये जा सकते हैं।

भारतीय शहरों में सालाना करीब 1.4 से 1.6 लाख टन शहरी कचरा निकलता है। साल 2016 से 2024 के बीच, शहरी निकायों में कचरा संग्रहण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका दायरा 44 प्रतिशत वार्डों से बढ़कर अब 97 प्रतिशत वार्डों तक पहुंच गया है, जो लगभग पूर्ण-विस्तार के नजदीक है। इसी वजह से शहरी निकायों के वाहनों का बेड़ा देश में सबसे बड़े संगठित वाहन बेड़े में से एक बन गया है। हालांकि, देश में 70 प्रतिशत से अधिक कचरा 'जनगणना श्रेणी-1' के शहरों (1 लाख से अधिक आबादी) से निकलता है, जो सालाना 3-4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के हालिया शोध के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या और कचरे की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए इन शहरों को 2030 तक डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए 80,000 नए वाहन चाहिये।

शहरी कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित कुल बजट का करीब आधा हिस्सा कचरा संग्रहण व ढुलाई पर खर्च होता है। इतने अधिक वित्तीय बोझ के अलावा डीजल या सीएनजी वाहनों से कचरा संग्रहण और ढुलाई का पर्यावरण पर असर पड़ता है। अमृतसर के उदाहरण के साथ सीईईडब्ल्यू का अध्ययन बताता है कि कचरा संग्रहण वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कितना लाभ दे सकता है। अभी अमृतसर में कचरा संग्रहण व ढुलाई में 200-220 चौपहिया डीजल वाहन इस्तेमाल होते हैं, जो रोजाना 400 टन से अधिक कचरे का प्रबंधन करते हैं। प्रतिदिन प्रति वाहन औसत उपयोग 15-20 किमी है। इस उपयोग स्तर पर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन अपने पूरे जीवनकाल में मौजूदा वाहनों के मुकाबले 25-30 फीसदी किफायती साबित होंगे, जिससे नगर निगम का सालाना ईंधन खर्च 60-80 फीसदी कम होगा।

भारतीय शहरों में आमतौर पर कचरा संग्रहण वाहन प्रतिदिन 15-55 किमी दूरी तय करते हैं, जिनमें तीन व चार पहिया वाहन शामिल हैं। प्रतिदिन प्रति वाहन 50-60 किमी अधिकतम उपयोग स्तर पर इ-तिपहिया वाहन सबसे किफायती विकल्प हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन डीजल व सीएनजी वाहनों के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। प्रत्येक इ-वाहन सालाना लगभग 83 किलोग्राम सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) और आधा टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन घटा सकता है।

कचरा संग्रहण वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का आधार काफी मजबूत है। चूंकि ये वाहन तय मार्गों पर चलते हैं और लौटकर डिपो में खड़े होते हैं, इसलिए इन्हें रात में चार्ज करना संभव है। इससे वाहनों की दूरी तय करने की चिंता खत्म होती है। लखनऊ, चेन्नई और इंदौर जैसे शहर कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इन सफलताओं को देश के सभी शहरों में लागू करने को एक सुनियोजित रोडमैप की जरूरत है।

सबसे पहले, शहरी स्थानीय निकायों को पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए इ-वाहनों के प्रति भरोसे में लेना चाहिए। कचरा प्रबंधन में विशेष काम शामिल होते हैं, खास तौर पर गीले कचरे के प्रबंधन में। इसलिए, पायलट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरे शहरों के अनुभवों से सीखने के साथ-साथ शहरस्तरीय कार्यशालाएं आयोजित हों। इससे अधिकारियों और वाहन संचालकों को जमीनी स्थितियों में इ-वाहनों की क्षमता, चार्जिंग जरूरतों और रखरखाव को समझने में मदद मिल सकती है।

दूसरा, शहरों को कचरा संग्रहण वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाने की चरणबद्ध योजनाएं बनानी चाहिए। शहरी निकाय अपने मौजूदा वाहनों की आयु, ईंधन के प्रकार और दैनिक उपयोग के आधार पर विवरण तैयार करें और पुराने वाहनों को हटाने के क्रम में इ-वाहन लाने का लक्ष्य तय करें। चरणबद्ध योजनाएं वाहन खरीद को राष्ट्रीय - राज्यों के इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी लक्ष्यों के साथ तालमेल लाने में मदद करेंगी।

तीसरा, नीतिगत प्रोत्साहनों का लक्ष्य बहुत सटीक होना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय ईवी नीतियां कचरा-संग्रहण वाहनों को विशेष सब्सिडी देकर शुरुआती लागत घटा सकती हैं। थोक खरीद के लिए संयुक्त निविदाओं के जरिए विभिन्न शहरों की मांगों को आपस में जोड़कर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है। कचरा संग्रहण वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राज्यों के स्तर पर विशेष आवंटन किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने 16वें वित्त आयोग के 'बिना शर्त अनुदान' के जरिए शहरों को वित्तीय स्वायत्तता दी है। यह अनुदान कचरा संग्रहण वाहन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में ऐसे रैंकिंग मापदंड जोड़े जा सकते हैं, जो कचरा संग्रहण में इ-वाहनों को प्रोत्साहित करें।

अभी से 50 प्रतिशत ईवी और 2027 से सिर्फ ईवी खरीदने की अनिवार्यता के साथ, भारत इस दशक के अंत तक कचरा संग्रहण के लिए 65 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन को लाने का लक्ष्य पा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की अगली बड़ी छलांग इन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों से आएगी।

प्रेरणा

अदम्य संकल्प से विज्ञान तक पहुँचा एक सपना

मानव इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, धैर्य और असफलताओं से भी पहचाना जाता है। रुडोल्फ डीजल का जीवन ऐसी ही एक प्रेरक गाथा है, जिसमें सपने, दुर्घटनाएँ, निराशा और फिर नवाचार की अद्भुत यात्रा समाहित है। उनका नाम आज जिस डीजल इंजन से जुड़ा है, वह केवल एक यांत्रिक आविष्कार नहीं, बल्कि वर्षों के समर्पण, जोखिम और अटूट विश्वास का परिणाम है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने कठिन परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उन्हें अपने संकल्प की कसौटी बना लिया।

रुडोल्फ डीजल का बचपन साधारण परिवेश में बीता, लेकिन उनके विचार बचपन से ही असाधारण थे। उन्हें चीज़ों को खोलकर देखने, समझने और फिर दोबारा जोड़ने में आनंद मिलता था। उनकी यह जिज्ञासा धीरे-धीरे विज्ञान और यांत्रिकी के प्रति गहरे लगाव में बदल गई। महज 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता-पिता से यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। यह केवल एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके भीतर आकार ले रही एक ठोस सोच थी। उस उम्र में जब अधिकांश किशोर भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं, डीजल का लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट था।

अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने जर्मनी का रुख किया, जो उस समय तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रगति का केंद्र माना जाता था। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ प्रयोगात्मक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मशीनों के साथ समय बिताकर उनके व्यवहार और सीमाओं को समझने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका जीवन लगभग पूरी तरह प्रयोगों और शोध के इर्द-गिर्द घूमने लगा। उनकी वर्कशॉप उनके लिए केवल काम करने की जगह नहीं, बल्कि विचारों को मूर्त रूप देने का मंदिर थी।

उस समय भाप इंजन का व्यापक उपयोग हो रहा था, लेकिन इन इंजनों की दक्षता सीमित थी। वे भारी थे, अधिक ईंधन खपत करते थे और उनका रखरखाव भी कठिन था। रुडोल्फ डीजल को यह स्वीकार्य नहीं था। उनका मानना था कि यदि इंजन के मूल सिद्धांतों पर नए सिरे से विचार किया जाए, तो अधिक शक्तिशाली और किफायती इंजन बनाया जा सकता है। यही सोच उन्हें लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती रही। कई प्रयोग असफल हुए, कई बार उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई।

इसी प्रयोगात्मक यात्रा के दौरान एक ऐसा दिन आया जिसने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। जब वे अपनी वर्कशॉप में इंजन पर काम कर रहे थे, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भयानक था कि पूरी वर्कशॉप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मशीनें नष्ट हो गईं, उपकरण इधर-उधर बिखर गए और स्वयं रुडोल्फ डीजल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। यह हादसा न केवल शारीरिक पीड़ा लेकर आया, बल्कि वर्षों की मेहनत भी एक झटके में नष्ट हो गई।

अधिकांश लोग ऐसे हादसे के बाद टूट जाते, लेकिन डीजल की सोच अलग थी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए भी उनका मन शांत नहीं था। वे बार-बार उसी प्रयोग के बारे में सोचते रहते थे, यह समझने की कोशिश करते थे कि गलती कहाँ हुई और भविष्य में उसे कैसे टाला जा सकता है। उन्होंने इस दुर्घटना को अपने जीवन की हार नहीं माना, बल्कि इसे सीखने का अवसर समझा। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास था कि असफलता केवल अस्थायी होती है, यदि मन में आगे बढ़ने का साहस हो।

लंबे इलाज और पुनर्वास के बाद जब वे फिर से खड़े होने में सक्षम हुए, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी वर्कशॉप लौटने का निर्णय लिया। टूटी हुई दीवारें और नष्ट हुए उपकरण उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सके। उन्होंने फिर से शुरुआत की, इस बार पहले से अधिक अनुभव, सावधानी और दृढ़ता के साथ। उन्होंने इंजन के दहन सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया और यह समझा कि यदि ईंधन को अत्यधिक संपीड़न में रखा जाए, तो वह बिना चिंगारी के स्वयं प्रज्वलित हो सकता है। यही विचार आगे चलकर डीजल इंजन के मूल सिद्धांत का आधार बना।

लगातार प्रयासों और संशोधनों के बाद उनके प्रयोग सफल होने लगे। उन्होंने ऐसा इंजन विकसित किया जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक टिकाऊ और कम ईंधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाला था। यह इंजन उद्योग जगत के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि साबित हुआ। जहाजों, रेल इंजनों, भारी वाहनों और बाद में बिजली उत्पादन में इस तकनीक का तेजी से उपयोग होने लगा। डीजल इंजन ने औद्योगिक विकास को नई गति दी और परिवहन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया।

रुडोल्फ डीजल का योगदान केवल एक तकनीकी आविष्कार तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वैज्ञानिक सोच और व्यावहारिक प्रयोग का सही मेल समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा नवाचार केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास से जन्म लेता है। आज के आधुनिक डीजल इंजन भले ही तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत हों, लेकिन उनके मूल सिद्धांत वही हैं, जिन्हें डीजल ने अपने अथक परिश्रम से विकसित किया था।

आज की नई पीढ़ी, जो तेजी से बदलती तकनीक और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने सपनों को आकार देने की कोशिश कर रही है, रुडोल्फ डीजल के जीवन से बहुत कुछ सीख सकती है। उनका जीवन सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। रुडोल्फ डीजल आज भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनका आविष्कार और उनकी सोच आज भी दुनिया को आगे बढ़ा रही है। हर वह मशीन जो डीजल के सिद्धांत पर चलती है, उनके संघर्ष, समर्पण और अदम्य संकल्प की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है।

जवाबदेही के दायरे में आएं टेक कंपनियां, बेरहम है डिजिटल दुनिया

सुबह की पहली किरण के साथ जब हम अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन अनलॉक करते हैं, तो हम केवल एक उपकरण नहीं खोलते, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो कभी सोती नहीं है। यह डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार है, उतनी ही बेरहम भी। आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया के गलियारों में बीत रहा है। हमारी पहचान, रिश्ते और समाज में प्रतिष्ठा अब हमारे पदचिह्नों यानी डिजिटल फुटप्रिंट्स से तय होती है, पर समस्या तब शुरू होती है जब ये पदचिह्न हमारी वर्तमान पहचान के लिए बोझ बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की, जिस पर दस साल पहले एक छोटा आरोप लगा था। अदालत ने उसे ससम्मान बरी कर दिया, लेकिन आज जब कोई कंपनी उसे नौकरी देने के लिए उसका नाम गूगल करती है, तो सबसे ऊपर वही पुरानी गिरफ्तारी की खबर चमकती है। यही वह बिंदु है जहां राइट टू बी फॉरगाटेन यानी भुला दिए जाने का अधिकार विलासिता नहीं, बल्कि जीने के अधिकार का हिस्सा बन जाता है।

डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग आज एक महामारी की तरह फैल चुका है। फेक न्यूज, ट्रोलिंग और साइबरबुलिंग ने वर्चुअल स्पेस को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। सबसे भयावह रूप तब सामने आता है, जब किसी की निजी जानकारी या तस्वीरें उसकी मर्जी के बिना सार्वजनिक कर दी जाती हैं। इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। यह केवल तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह एक इंसान की गरिमा पर सीधा हमला है। जब कोई अपमानजनक सामग्री एक बार वायरल हो जाती है, तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से मरता नहीं है, वह बस दबा रहता है और समय-समय पर बाहर आता रहता है।

यहीं पर राइट टू बी फॉरगाटेन की अवधारणा उम्मीद की किरण है। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पुराने, अप्रासंगिक या गलत डिजिटल रिकॉर्ड्स को हटवा सके। यूरोपीय संघ का एक कानून इस मामले में एक मिसाल है। वहां के एक चर्चित मामले में यह तय हुआ कि अगर कोई जानकारी अब जरूरी नहीं है, तो उसे सर्च रिजल्ट्स से हटाना होगा। भारत में भी इस अधिकार की सुगबुगाहट तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार तो माना, लेकिन राइट टू बी फॉरगाटेन अभी भी एक कानूनी धुंध में फंसा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में माना कि एक व्यक्ति को अपनी पुरानी गलतियों या विवादों से आगे बढ़ने का हक है। क्या हमारे पास इसके लिए कोई ठोस कानून है?

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस दिशा में एक कदम जरूर है। यह डाटा मिटाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। जब कोई व्यक्ति अपना डाटा हटवाने की मांग करता है, तो उसके सामने अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायिक पारदर्शिता की दीवार खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पर, क्या एक भ्रष्ट नेता यह कह सकता है कि लोग उसके पुराने घोटाले भूल जाएं, क्योंकि अब वह सुधर गया है? निश्चित रूप से नहीं। जनता को जानने का अधिकार और सार्वजनिक हित हमेशा निजी निजता से ऊपर रहेगा, लेकिन एक सामान्य नागरिक, जो किसी झूठे मुकदमे या निजी विवाद का शिकार हुआ है, उसे अदालतों के चक्कर क्यों काटने पड़ें? हमारे वर्तमान कानून में एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया की कमी है, जो टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहरा सके।

इस जटिल समीकरण में अब एआई ने प्रवेश किया है। एआई के दुरुपयोग का सबसे वीभत्स रूप डीपफेक है। आज किसी भी आम इंसान का चेहरा किसी अश्लील वीडियो या भड़काऊ भाषण के साथ जोड़ना बच्चों का खेल बन गया है। एआई एल्गोरिदम आज इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपकी पसंद-नापसंद को भांप लेते हैं और आपको उसी दिशा में ले जाते हैं, जो वे चाहते हैं। नफरत भरे कंटेंट पर इंगेजमेंट ज्यादा आती है, इसलिए एल्गोरिदम उसे बढ़ावा देते हैं। यह एआई का वह चेहरा है, जो समाज को बांट रहा है। इसी एआई में समाधान भी छिपा है। अगर हम एआई को सही नीयत के साथ इस्तेमाल करें, तो यह एक डिजिटल रक्षक बन सकता है। जिस रफ्तार से डिजिटल मीडिया पर डाटा अपलोड होता है, उसे इंसान कभी मॉनिटर नहीं कर सकते। यहां एआई एक फिल्टर की तरह काम कर सकता है। यह आपत्तिजनक कंटेंट, डीपफेक और फेक न्यूज को उसके फैलने से पहले ही पहचान कर ब्लाक कर सकता है। राइट टू बी फॉरगाटेन को लागू करने में एआइ मददगार साबित हो सकता है। जरूरत एक ऐसी नीति की है, जो टेक कंपनियों को बाध्य करे कि वे अपने एआई माडल्स को सुरक्षा और निजता के अनुकूल बनाएं।

भारत को राइट टू बी फॉरगाटेन के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करना होगा। यह केवल कागजी अधिकार न हो, एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां एक क्लिक पर पीड़ित की सुनवाई हो। हमें विशेष डिजिटल ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है जहां तकनीकी विशेषज्ञ और कानूनी जानकार मिलकर त्वरित फैसले लें। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वह उन प्लेटफॉर्म्स पर भारी जुर्माना लगा सके, जो आदेश मिलने के बाद भी डाटा नहीं हटाते। कानून में स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में डाटा हटाया जा सकता है और कहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि होगा?

एक और महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि टेक कंपनियों के लिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अनिवार्य हो, ताकि पता चले कि उन्होंने कितने अनुरोध स्वीकार किए और कितने खारिज। हमें एक ऐसी डिजिटल संस्कृति विकसित करनी होगी, जहां हम दूसरों की निजता का सम्मान करें। कानून अपना काम करेगा, एआई अपना सुधार करेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को एक दूसरा मौका मिलने का हक है।

अभियान

केदारनाथ के बाद बदरीनाथ के लिए हेली सेवा, चारधाम यात्रा में नई उड़ान

उत्तराखंड सरकार लगातार चारधाम यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से चारधाम की यात्रा पर आते हैं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, लंबी पैदल यात्राओं तथा मौसम की अनिश्चितता के बावजूद आस्था के साथ इन पवित्र धामों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सरकार का उद्देश्य यही रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे और साथ ही उनकी यात्रा कम से कम कष्टकारी हो। इसी क्रम में केदारनाथ धाम के बाद अब बदरीनाथ धाम के लिए भी हेली शटल सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है और जिम्मेदारी थंपी एविएशन को सौंपी गई है, जिससे आने वाले यात्रा सीजन में बदरीनाथ पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगा।

चारधाम यात्रा का शुभारंभ हर वर्ष अप्रैल–मई में धामों के कपाट खुलने के साथ होता है। उस समय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने में कई बार घंटों का जाम, खराब मौसम और पहाड़ी रास्तों की कठिनाई यात्रियों के लिए चुनौती बन जाती है। विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा शारीरिक रूप से काफी थकाऊ हो जाती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवाएं शुरू की थीं, जो फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से संचालित होती हैं। इन सेवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है और यही अनुभव अब बदरीनाथ धाम के लिए भी दोहराया जा रहा है।

बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित हेली शटल सेवा गौचर से संचालित की जाएगी। गौचर से बदरीनाथ तक की एकतरफा हवाई यात्रा में लगभग 22 मिनट का समय लगेगा, जो सड़क मार्ग से कई घंटों की यात्रा की तुलना में बेहद कम है। इस सेवा का अनुमानित किराया लगभग 11,000 रुपये रखा गया है, जो केदारनाथ की हेली सेवाओं की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण दूरी और उड़ान समय बताया जा रहा है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा में अधिकतम उड़ान समय करीब 15 मिनट का होता है, जबकि बदरीनाथ के लिए यह समय अधिक है। बावजूद इसके, श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा समय, श्रम और जोखिम के लिहाज से बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य केवल सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना भी है। पिछले वर्षों में हेली सेवाओं के दौरान कुछ दुर्घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा मानकों को और सख्त किया। उड़ानों की संख्या में कटौती की गई, पायलटों और तकनीकी स्टाफ के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए और किरायों में भी वृद्धि करनी पड़ी। इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए बदरीनाथ के लिए शुरू की जा रही हेली सेवाओं में भी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

बदरीनाथ हेली शटल सेवा के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल रखी जाएगी। श्रद्धालु आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान में केदारनाथ हेली सेवाओं के लिए किया जाता है। इससे दलालों और अवैध बुकिंग की संभावनाओं पर रोक लगेगी और श्रद्धालुओं को वास्तविक किराये पर सीधी सुविधा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल बुकिंग प्रणाली से यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा और व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बनेगी। मुख्य अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूकाडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि बदरीनाथ के लिए हेली शटल सेवा के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और यात्रा सीजन के दौरान गौचर से बदरीनाथ के लिए इन सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवाओं के संचालन में सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और मौसम की स्थिति को देखते हुए ही उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए उड़ानों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

केदारनाथ हेली सेवा के किराये को लेकर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी चर्चा रहती है। पिछले वर्ष हेली दुर्घटनाओं के बाद दूसरे चरण की सेवाओं में लगभग 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी और किरायों में करीब 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई थी। इससे कई श्रद्धालुओं को आर्थिक रूप से असुविधा हुई थी, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया था। इस वर्ष केदारनाथ धाम के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है और संभावना है कि हेली सेवाओं की संख्या सीमित ही रहेगी। चूंकि पिछले वर्ष किराये में पहले ही वृद्धि हो चुकी थी, इसलिए इस बार टेंडर में किराया पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है। हालांकि वास्तविक दरें टेंडर खुलने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगी।

बदरीनाथ के साथ-साथ यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली शटल सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि यमुनोत्री के लिए कुछ तकनीकी कारणों के चलते अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वहां हेलीपैड और उड़ान मार्ग से जुड़ी कुछ तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियां हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में यमुनोत्री धाम के लिए भी हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, ताकि चारों धामों की यात्रा एक समान रूप से सुविधाजनक हो सके।

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, होटल, परिवहन, गाइड, घोड़ा-खच्चर व्यवसाय और छोटे व्यापारियों की आजीविका इससे जुड़ी होती है। हेली शटल सेवाओं के विस्तार से जहां एक ओर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि पर्यावरण और स्थानीय संतुलन पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

कुल मिलाकर, केदारनाथ के बाद बदरीनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा की शुरुआत चारधाम यात्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा भी बढ़ेगी। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ यदि यह सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित होती हैं, तो आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। आस्था और आधुनिक सुविधा का यह संगम उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

इंडियन ऑयल पाइपलाइन में सेंध से उजागर हुआ संगठित पेट्रोल चोरी का जटिल नेटवर्क

जीएनएस)। राजस्थान के ब्यावर जिले से सामने आया पेट्रोल चोरी का यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक निगरानी व्यवस्था और संगठित अपराध के बढ़ते हौसलों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। लालपुरा घाटे के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भूमिगत पाइपलाइन में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से सेंध लगाई गई, वह किसी छोटे-मोटे अपराधी के बस की बात नहीं लगती। पाइपलाइन में अवैध रूप से वाल्व लगाकर लगभग 120 मीटर लंबी समानांतर लाइन बिछाई जाना इस बात का संकेत है कि यह चोरी अचानक नहीं, बल्कि पूरी योजना, तकनीकी समझ और लंबे समय की तैयारी के साथ की जा रही थी।

यह घटना सेंदड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां आयुषी पाइपलाइन के जरिए लंबे समय से पेट्रोल चोरी का गोरखधंधा चल रहा था। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन आमतौर पर बेहद सुरक्षित मानी जाती है, जिसमें दबाव, प्रवाह और मात्रा पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी प्रणाली लगी होती है। ऐसे में इस प्रणाली में गड़बड़ी सामने आना और फिर जांच के दौरान पाइपलाइन में पंचर और अवैध कनेक्शन का मिलना यह दर्शाता है कि चोरों ने न सिर्फ पाइपलाइन के सटीक लोकेशन की जानकारी हासिल की थी, बल्कि वे निगरानी प्रणाली की सीमाओं से भी वाकिफ थे।

बताया जा रहा है कि चोरों ने मुख्य पाइपलाइन में एक विशेष प्रकार का वाल्व फिट किया था, जिसके जरिए जरूरत के हिसाब से पेट्रोल निकाला जा सकता था। इसी वाल्व से करीब 120 मीटर लंबी एक अलग लाइन बिछाई गई थी, जो मुख्य पाइपलाइन के समानांतर चल रही थी। इस समानांतर लाइन के जरिए पेट्रोल को सुरक्षित दूरी पर किसी अन्य स्थान तक पहुंचाया जाता था, ताकि चोरी करते वक्त मुख्य पाइपलाइन के आसपास ज्यादा गतिविधि न दिखे और किसी को शक न हो। यह तरीका इतना सुनियोजित था कि पहली नजर में यह एक नियमित तकनीकी संरचना जैसा प्रतीत हो सकता था।

शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह चोरी कई दिनों या शायद कई महीनों से चल रही थी। यदि ऐसा

है, तो इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में पेट्रोल अवैध रूप से निकाला गया होगा, जिसकी कीमत लाखों या करोड़ों रुपये में हो सकती है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि इससे पाइपलाइन की सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखिम और आम लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो सकता था। पेट्रोल जैसी ज्वलनशील सामग्री की पाइपलाइन में अवैध छेड़छाड़ से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तकनीकी निगरानी प्रणाली में जब असामान्य गतिविधि दर्ज हुई, तब कंपनी की जांच टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचते ही टीम ने विस्तृत तकनीकी जांच शुरू की, जिसमें पाइपलाइन के दबाव, प्रवाह और संरचना की बारीकी से जांच की गई। इसी दौरान पाइपलाइन में किया गया पंचर और उससे जुड़ा अवैध वाल्व सामने आया। यह देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए कि किस तरह इतनी सफाई और तकनीकी समझ के साथ चोरी को अंजाम दिया जा रहा था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए इंडियन ऑयल की तकनीकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन में किए गए पंचर को क्लैंप लगाकर दुरुस्त करने का काम शुरू किया। इस दौरान मुख्य प्रचालन प्रबंधक अमित अग्रवाल, प्रबंधक शिवम शर्मा, पवन वर्मा, सीपी पारीक सहित कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पाइपलाइन की मरम्मत के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाए। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। सेंदड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस चोरी के पीछे कौन लोग हैं, वे स्थानीय हैं या किसी बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा हैं, और चोरी किया गया पेट्रोल कहां और कैसे बेचा जा रहा था। पुलिस के लिए यह भी एक चुनौती है कि इतनी बड़ी पाइपलाइन में सेंध लगाने के लिए जरूरी उपकरण, तकनीकी जानकारी और मानव संसाधन आखिर कहां से आए। पुलिस और कंपनी प्रशासन दोनों का मानना है कि यह काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। इसमें संगठित गिरोह की भूमिका होने की प्रबल आशंका है, जिसमें तकनीकी जानकार, स्थानीय सहयोगी और पेट्रोल की अवैध बिक्री से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। यह भी संभव है कि चोरी किए गए पेट्रोल को आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बेचा जा रहा हो या फिर इसे किसी अन्य राज्य तक सप्लाई किया जा रहा हो। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी मजबूत मानी जाने वाली पाइपलाइन सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोरी कैसे संभव हो पा रही है। हालांकि इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से विविध देश में हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है। कई बार दूरदराज या सुनसान इलाकों में पाइपलाइन होने के कारण चोरों को मौका मिल जाता है।

शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि चोरी के लिए चुना गया स्थान अपेक्षाकृत सुनसान था, जहां लोगों की आवाजाही कम रहती है। यही वजह है कि चोर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहे। इस दौरान न तो किसी स्थानीय ने शक जताया और न ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई, जिससे मामला तुरंत उजागर हो सके। लेकिन तकनीकी निगरानी में आई गड़बड़ी ने आखिरकार इस चोरी के राज से पर्दा उठा दिया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। पाइपलाइन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल लोकेशन डेटा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस पूरे मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है, जिसने पाइपलाइन की लोकेशन और तकनीकी जानकारी चोरों तक पहुंचाई हो। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कंपनी प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। इसमें ड्रोन सर्विलांस, रियल-टाइम डेटा एनालिसिस और स्थानीय स्तर पर गश्त बढ़ाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान के ब्यावर जिले में सामने आया यह मामला सिर्फ एक चोरी की घटना नहीं है, बल्कि यह बताता है कि संगठित अपराधी किस तरह नई-नई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल कर सरकारी और सार्वजनिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह घटना प्रशासन, तेल कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी है कि सतर्कता में थोड़ी सी भी चूक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

फिलहाल पुलिस और कंपनी की संयुक्त जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पेट्रोल चोरी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद कितने बड़े स्तर पर इस गोरखधंधे की परतें खुलती हैं और क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बन पाती है या नहीं।

कोटा में इमारत ढहने से उजड़ा जीवन, मासूम और छात्र की मौत ने झकझोरा शहर

जीएनएस)। राजस्थान के शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा में बुधवार रात हुआ हादसा पूरे शहर को सन्न कर गया। रोज़ की तरह चहल-पहल से भरे जवाहर नगर थाना क्षेत्र के इंद्र विहार इलाके में रात करीब 8:45 बजे अचानक चार मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। देखते ही देखते खुशियों, रौनक और रोज़मर्रा की आवाज़ों से भरा इलाका चीख-पुकार, धूल और अफरा-तफरी में बदल गया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा न सिर्फ एक इमारत के गिरने की कहानी है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

हादसे में जिन दो लोगों की जान गई, उनमें एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़का शामिल है, जो इलाके में भीख मांगकर अपना गुज़ारा करता था। रोज़ की तरह वह भी रेस्टोरेंट और दुकानों के आसपास मौजूद था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि वही जगह उसकी जिंदगी की आखिरी ठिकाना बन जाएगी। दूसरी मौत 20 वर्षीय युवक की हुई, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और कोटा में रहकर निजी कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

कर रहा था। कोटा, जो देशभर से लाखों छात्रों के सपनों का शहर है, उसी शहर में एक होनहार छात्र की इस तरह असमय मौत ने हर किसी को झकझोर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे से ठीक पहले एक तेज धमाके जैसी आवाज़ आई और उसके कुछ ही सेकंड बाद इमारत का एक हिस्सा ढह गया। ग्राउंड फ्लोर पर "दिल्ली स्पाइस रोल हट" नाम से एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, जहां उस समय काफी भीड़ थी। नीचे दुकानों में ग्राहक और कर्मचारी मौजूद थे, वहीं पार्किंग एरिया में भी लोग बैठे हुए थे। अचानक मलबा गिरने से लोग संभल भी नहीं पाए और कई लोग उसके नीचे दब गए। धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ देर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी ने पुलिस को फोन किया, तो किसी ने एंबुलेंस बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग मलबे में दबे लोगों को अपने हाथों से निकालने में जुट गए। थोड़ी ही देर में पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जाने लगा, ताकि नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल था, हर कोई अपने किसी परिचित को ढूंढ रहा था, कोई रो रहा था तो कोई दुआ कर रहा था। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि अस्पताल में कुल 11 लोगों को लाया गया था, जिनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज जारी है और छह की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक, कई घायलों को सिर, सीने और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल परिसर में भी रातभर बेचैनी का माहौल रहा, जहां परिजन और साथी छात्र अपनों की सलामती के लिए परेशान दिखे।

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर इतनी मजबूत दिखने वाली इमारत अचानक कैसे गिर गई। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, वह और भी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि जिस इमारत का हिस्सा गिरा, उसके पीछे वाली इमारत में जेसीबी से खुदाई और निर्माण कार्य चल रहा था। इस भारी मशीनरी के कारण जमीन में कंपन हुआ, जिससे पहले से कमजोर हो चुकी इमारत की नींव पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और वह ढह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा था और कई बार कंपन इतना तेज होता था कि आसपास की इमारतें हिलती महसूस होती थीं। स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि संबंधित इमारत पुरानी थी और उसमें समय-समय पर मरम्मत या संरचनात्मक जांच नहीं कराई गई। इसके बावजूद उसमें रेस्टोरेंट और दुकानें चल रही थीं, जहां रोज़ सैकड़ों लोग आते-जाते थे। सवाल यह भी है कि नगर निगम और प्रशासन की ओर से इस इमारत की सुरक्षा को लेकर कोई निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। अगर समय रहते चेतावनी दी जाती या निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती, तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था।

तेजी के हफ्ते में दिग्गज कंपनियों की वैल्यू में उछाल, आठ शीर्ष कंपनियों का मार्केट कैप 4.55 लाख करोड़ बढ़ा

जीएनएस)। मुंबई। शेयर बाजार में बीते सप्ताह देखने को मिली मजबूत तेजी ने देश की प्रमुख कंपनियों की बाजार हैसियत में बड़ा इजाफा कर दिया। सेंसेक्स में 3.53 फीसदी की बढ़त के साथ आई इस तेजी का सबसे अधिक फायदा शीर्ष 10 में शामिल आठ कंपनियों को मिला, जिनके संयुक्त बाजार पूंजीकरण में करीब 4.55 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह तेजी निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत बनी, वहीं चुनिंदा सेक्टरों में मुनाफावसूली का असर भी देखने को मिला।

इस अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और उसका बाजार पूंजीकरण करीब 1.42 लाख करोड़ रुपये बढ़कर लगभग 19.63 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में मजबूती से आगे बनी रही। कंपनी के शेयरों में आई इस तेजी से निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। इसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के निवेशकों के लिए भी यह सप्ताह राहत भरा साबित हुआ। एलआईसी की बाजार हैसियत में करीब 64,900 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका कुल मार्केट कैप लगभग 5.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर में भी मजबूती का माहौल रहा। भारती एयरटेल के बाजार पूंजीकरण में करीब 52,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जबकि आईसीआईसीआई

बैंक की वैल्यू में 52,400 करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा देखा गया। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में आई इस तेजी ने पूरे बाजार को सहारा दिया और निवेशकों की धारणा को सकारात्मक बनाए रखा।

बजाज फाइनेंस ने भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया और कंपनी के बाजार पूंजीकरण में करीब 48,600 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की वैल्यू में भी लगभग 45,400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों ने भी बाजार की तेजी का लाभ उठाया और इनके मार्केट कैप में क्रमशः 32,300 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की मजबूती आई।

हालांकि, यह सप्ताह आईटी सेक्टर के लिए दबाव भरा रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में करीब 88,000 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इंफोसिस की वैल्यू लगभग 63,000 करोड़ रुपये घट गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक टेक शेयरों में कमजोरी, ऊंचे वैल्यूएशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा।

कुल मिलाकर, बीता सप्ताह शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया, जहां अधिकांश दिग्गज कंपनियों ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया। मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, जबकि उसके बाद एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल का स्थान है। बाजार की यह तेजी आने वाले दिनों में निवेशकों की धारणा और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी।

साइबर सुरक्षा बनी भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती, डेटा चोरी से कारोबार की रफ्तार पर खतरा

जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय कॉरपोरेट जगत के सामने जोखिमों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है। 'FICCI–EY रिस्क सर्वे 2026' की रिपोर्ट बताती है कि देश के आधे से अधिक उद्यमी और शीर्ष अधिकारी साइबर अटैक और डेटा चोरी को अपनी कंपनियों की वृद्धि में सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं। सर्वे के मुताबिक 51 फीसदी बिजनेस लीडर्स के लिए इस समय डिजिटल ब्रीच और साइबर हमले सबसे गंभीर जोखिम हैं, जो न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कंपनियों की साख और ग्राहकों के भरोसे को भी कमजोर करते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तकनीक और बिजनेस ऑपरेशंस अब पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता ने जहां कारोबार को नई ऊंचाइयां दी हैं, वहीं जोखिमों का दायरा भी बढ़ा दिया है। करीब 61 फीसदी उद्योग प्रमुखों का कहना है कि तेज डिजिटल बदलाव उनके बाजार, प्रतिस्पर्धा और कारोबारी रणनीति को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी बड़े साइबर हमले का असर केवल आईटी सिस्टम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर ब्रांड इमेज, ग्राहक विश्वास और भविष्य की ग्रोथ पर पड़ता है। सर्वे के अनुसार डेटा चोरी और इनसाइडर फ्रॉड को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। कंपनियां अब केवल बाहरी हैकर्स से ही नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर होने वाली चूक और दुरुपयोग से भी जूझ रही हैं। यही वजह है कि साइबर सुरक्षा अब आईटी विभाग तक सीमित विषय नहीं रह गया है, बल्कि बोर्डरूम की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। कई कंपनियां साइबर जोखिम को रणनीतिक जोखिम मानते हुए अपने निर्णयों में इसे प्रमुखता से शामिल कर रही हैं।

रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की ओर भी इशारा करती है। सर्वे में शामिल 60 फीसदी अधिकारियों का मानना है कि यदि कंपनियां AI को नजरअंदाज करती हैं तो वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर 54 फीसदी अधिकारियों ने AI से जुड़े गवर्नेंस, डेटा प्राइवेसी और नैतिक जोखिमों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि AI के गलत या अनियंत्रित उपयोग से कानूनी और प्रतिष्ठात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए स्पष्ट नीतियों और मजबूत निगरानी तंत्र की जरूरत है।

रिपोर्ट में स्किल्ड टैलेंट की कमी को भी एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में कई कंपनियां ऐसे प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी से जूझ रही हैं, जो साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और AI जैसे क्षेत्रों में दक्ष हों। इसके साथ ही उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास की कमी भी लंबे समय में कंपनियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आज जोखिम प्रबंधन किसी एक घटना या संकट से निपटने तक सीमित नहीं रह गया है।

संगम की गोद में समर्पित हुईं अजित पवार की अस्थियां, श्रद्धा और शोक के बीच भावुक विदाई

जीएनएस)। प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर रविवार, 8 फरवरी 2026 का दिन श्रद्धा, आस्था और गहरे शोक का साक्षी बना, जब महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक नेता अजित पवार की अस्थियों का विधि-विधान से विसर्जन किया गया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अस्थियां प्रवाहित होते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। यह क्षण न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व को अंतिम विदाई देने का था, बल्कि एक युग के समापन का भी प्रतीक बन गया।

रविवार सुबह अजित पवार का परिवार महाराष्ट्र के बारामती से चार्टर्ड विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचा। सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट पर उतरते ही माहौल गमगीन हो गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच परिवार को सीधे संगम की ओर ले जाया

गया। एयरपोर्ट से संगम तक का पूरा रास्ता शांत और गंभीर वातावरण में तय हुआ, मानो शहर भी इस शोक में सहभागी हो। लोगों की निगाहें उस वाहन पर टिकी थीं, जिसमें अस्थि कलश रखा था।

इस पूरे अनुष्ठान में सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला, जब अजित पवार के पुत्र जय पवार नंगे पांव अस्थि कलश लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर गहरा दुख, आंखों में आंसू और कदमों में संयम था। नंगे पांव चलना मानो पिता के प्रति श्रद्धा और अंतिम कर्तव्य का प्रतीक बन गया। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे और कई की आंखों से आंसू छलक पड़े।

परिवार और समर्थकों का काफिला सीधे संगम के वीआईपी घाट पहुंचा, जहां पुरोहितों ने पूरे विधि-विधान से अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न कराई। वैदिक मंत्रों की गूंज, धूप-दीप की सुगंध और संगम की शांत लहरों के बीच दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहारा बनकर खड़े नजर आए। राजनीतिक जीवन में कठोर फैसले लेने वाले अजित पवार को अंतिम विदाई के क्षणों में हर कोई नम आंखों से याद कर रहा था।

इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक भी मौजूद रहे। सभी ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत नेता को याद किया। संगम तट पर खड़े लोग यह महसूस कर रहे थे कि राजनीति से परे, यह एक बेटे द्वारा पिता को दी जा रही अंतिम विदाई है, जिसमें सत्ता, पद और विचारधाराएं सब पीछे छूट गई थीं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अजित पवार की अस्थियों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर गुजरी और हर स्थान पर समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रविवार को प्रयागराज संगम पर जय पवार और परिवार की मौजूदगी में इस यात्रा का विधिवत समापन हुआ। यह यात्रा अजित पवार की राष्ट्रीय पहचान और उनके प्रभाव को दर्शाने वाली मानी गई।

गौरतलब है कि अजित पवार का निधन एक दुखद विमान हादसे में हुआ था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस दुर्घटना में उनके साथ चार अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। 29 जनवरी 2026 को बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उस दिन से लेकर संगम में अस्थि विसर्जन तक, शोक की यह यात्रा लगातार लोगों के दिलों को छूती रही। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के साथ ही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत मिला।

भावनगर मंडल के अंतर्गत चलने वाली तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए भावनगर मंडल से होकर चलने वाली तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए गए हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09018 वेरावल – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस – वेरावल साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी

तरह, ट्रेन संख्या 09207 बान्द्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस को 27 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09216 भावनगर – गांधीग्राम दैनिक अनारक्षित स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम –भावनगर टर्मिनस दैनिक अनारक्षित स्पेशल को भी 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

उपर्युक्त सभी आरक्षित ट्रेनों के विस्तारित फेरों की बुकिंग 08 फरवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ट्रेनों के ठहराव के समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर मंडल के सिहोर जं. पर साहसिक कार्यः प्वाइंट्समैन ने चलती ट्रेन से गिरती युवती की बचाई जान

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत सिहोर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 08 फरवरी, 2026 (रविवार) की सुबह सतर्कता और साहस की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। चलती ट्रेन संख्या 59229 बोटाद–भावनगर दैनिक पैसेंजर से उतरने के दौरान संतुलन खोकर गिर रही एक युवती की जान स्टेशन पर तैनात सतर्क प्वाइंट्समैन ने अपनी तत्परता से बचा ली।

यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि युवती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने वाली थी, लेकिन प्वाइंट्समैन ने बिना एक पल

गंवाए तुरंत दौड़कर उसे खींच लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ले आए। इस फुर्तीले और साहसिक बचाव कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवती चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके पर उपस्थित प्वाइंट्समैन श्री राज कुमार ने अपनी सतर्कता, फुर्ती और सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल कार्रवाई की, जिससे एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। इस घटना को ट्रेन में सवार यात्रियों एवं प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने स्तब्ध होकर देखा।

यह घटना चलती ट्रेनों में चढ़ने या उतरने के दौरान होने वाले खतरों को रेखांकित करती है। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर दुर्घटनाएं इसी प्रकार की लापरवाही के कारण होती हैं, जब यात्री ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले उतरने या चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं। कई बार भारी सामान के साथ चढ़ने-उतरने से संतुलन बिगड़ जाता है और गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही सुरक्षित रूप से चढ़ें अथवा उतरें तथा रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

सूरत में महिला सशक्तिकरण की दौड़, भारतीय जैन संगठन की गर्ल्स हाफ मैराथन में 5,000 से अधिक प्रतिभागियों का उत्साह

जीएनएस)। सूरत। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम रविवार, 8 फरवरी की सुबह सूरत में देखने को मिला, जब भारतीय जैन संगठन (BJS), सूरत द्वारा भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, वेसु परिसर में भव्य गर्ल्स हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे शुरू हुए इस आयोजन में 5,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं ने भाग लेकर यह संदेश दिया कि आज की बेटी न केवल अपने सपनों की ओर दौड़ रही है, बल्कि समाज को नई दिशा देने के लिए भी तैयार है। आयोजन स्थल पर सुबह 6 बजे से ही प्रतिभागियों की चहल-पहल शुरू हो गई थी और पूरा परिसर उत्सव, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रहा था।

इस मैराथन के अंतर्गत 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी, ताकि हर आयु वर्ग की बालिकाएं और महिलाएं इसमें सहजता से भाग ले सकें। सूरत शहर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ अमरोली, कतारगाम, पर्वत पाटिया और सचिन जैसे दूर-दराज़ इलाकों से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचीं। कई बालिकाएं अपने माता-पिता के साथ आई थीं, तो कई महिलाएं अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनीं। दौड़ से पहले उत्साह से भरे चेहरों, रंग-बिरंगे परिधानों और हाथों में लगाए गए प्रेरणादायक संदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का मंच है।

कार्यक्रम का शुभारंभ नवकार महामंत्र और राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिससे वातावरण में आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति की भावना एक साथ महसूस की गई। इसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मैराथन की औपचारिक शुरुआत की गई।

हरी झंडी दिखाते ही पहले 5 किलोमीटर दौड़ के प्रतिभागी पूरे जोश के साथ आगे बढ़े और उसके बाद 2 किलोमीटर दौड़ की प्रतिभागियों को रवाना किया गया। पूरे मार्ग में सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, जलपान और स्वयंसेवकों की सक्रिय उपस्थिति ने आयोजन को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखा। दौड़ के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास, मुस्कान और दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था, जिसने दर्शकों और आयोजकों सभी को भावुक और प्रेरित कर दिया।

इस आयोजन का मूल उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नियमित व्यायाम और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास का संदेश देना था। कई प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें न केवल शारीरिक मजबूती मिलती है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे सशक्त महसूस करती हैं। समाज में बेटियों की भूमिका को लेकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में ऐसे कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं।

इस गरिमामय अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सूरत शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत, सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी, शासक पक्ष नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, सूरत महानगरपालिका की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती गायत्री जरीवाला, श्रीमती संध्या गहलोत, ब्रह्मकुमारी संस्था से वनिता दीदी, श्रीमती सिद्धी जौहरी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। अतिथियों ने अपने संबोधन में भारतीय जैन संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मविश्वासी बनाने के लिए ऐसे आयोजन समय की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं स्वस्थ और आत्मनिर्भर होंगी, तभी समाज और राष्ट्र सशक्त बनेंगे।

भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर सांखला, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप चोपड़ा, मंत्री दीपक चोपड़ा, भारतीय जैन संगठन सूरत के अध्यक्ष अजय अजमेर सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन, विशाल सुराणा, सुरेश गोंडलिया, त्रिओम किशोर गन्ना, मनहर संस्परा, हस्तिमल्ल बांठिया, कुंज पंसारी, सनबो रंग, कैलाश जैन, विकास दोषी, संजय बोथरा और अनिल चंडालिया सहित शहर के अनेक सामाजिक और संगठनात्मक प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्वयंसेवकों की टीम ने पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, व्यवस्था और सहभागिता का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया।

मैराथन के समापन पर विभिन्न आयु वर्गों में विजेता रहीं बालिकाओं और महिलाओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के करकमलों द्वारा मेडल और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान विजेताओं के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी, वहीं अन्य प्रतिभागियों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया और आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

कुल मिलाकर, भारतीय जैन संगठन, सूरत की यह गर्ल्स हाफ मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता का एक प्रेरणादायक अभियान बनकर उभरी। यह आयोजन सूरत शहर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए यह संदेश छोड़ गया कि जब बेटियों को अवसर, मंच और प्रोत्साहन मिलता है, तो वे आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं।

दीप दर्शन विद्या संकुल की प्रदर्शनी में बच्चों की कल्पनाशक्ति और सीख का जीवंत उत्सव

जीएनएस)। सूरत। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के अनुभव, सोच और रचनात्मकता से जुड़े—इसी सोच को साकार करता एक भव्य आयोजन दीप दर्शन विद्या संकुल में देखने को मिला, जहां "प्रोजेक्ट्स वंडरलैंड & आर्ट फिएस्टा" नामक परियोजना प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को आयोजित इस प्रदर्शनी में GSEB प्राइमरी सेक्शन (इंग्लिश मीडियम) के विद्यार्थियों ने जिस आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, उसने अभिभावकों, शिक्षाविदों और अतिथियों को गहराई से प्रभावित किया। पूरा विद्यालय परिसर उस दिन ज्ञान, कला और नवाचार के रंगों से सराबोर नजर आया। सुबह से ही विद्यालय में चहल-पहल शुरू हो गई थी। विद्यार्थी अपने-अपने स्टॉल सजाने में जुटे थे, कहीं चार्ट्स लगाए जा रहे थे तो कहीं मॉडल्स को अंतिम रूप दिया जा रहा था। अभिभावकों की उत्सुक निगाहें और बच्चों के चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास इस आयोजन की सफलता की पहली झलक दे रहा था। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता, विषयगत समझ और व्यावहारिक ज्ञान को सामने लाना था, जिसमें विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की मेहनत साफ दिखाई दी।

इस अवसर पर वी.टी. चौकसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर वैदेही भ्रमभट्ट और श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट बी.एड कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. बिन्नी मेहता अपने इंटर्न्स के साथ उपस्थित रहीं। इसके साथ ही

स्पेस वॉक इंस्टिट्यूट की ओर से स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर्स श्री ओंकार कपूते और सुश्री सोनाली त्रिपाठी की विशेष उपस्थिति ने प्रदर्शनी को और अधिक ज्ञानवर्धक बना दिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उनके प्रोजेक्ट्स को देखा और उनकी सोच की खुले दिल से सराहना की।

कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रेरणादायक क्षण के साथ हुई, जब विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य प्रतिकृति का अनावरण किया गया। इस प्रतिकृति का अनावरण विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार श्री सवजीभाई पटेल, संचालक श्री दशरथभाई पटेल, श्री तुषारभाई पटेल, आचार्या कृतिबेन देसाई तथा उपाचार्य श्री ऋषिकेशभाई कोल्हापुरे के करकमलों द्वारा किया गया। यह मॉडल न केवल तकनीकी कौशल का उदाहरण था, बल्कि बच्चों में राष्ट्रभक्ति और इतिहास के प्रति समझ को भी दर्शा रहा था।

कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेज़ी, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, स्पेस एवं टेक्नोलॉजी, सेंसर आधारित प्रोजेक्ट्स सहित अनेक विषयों पर आधारित प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। बच्चों ने अपने मॉडल्स और चार्ट्स के माध्यम से जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाया। उनकी प्रस्तुति में आत्मविश्वास, स्पष्टता और विषय की गहराई साफ झलक रही थी। कई विद्यार्थी आगंतुकों के सवालों का उत्तर इतनी सहजता से दे रहे थे कि यह महसूस हो रहा था कि उन्होंने केवल याद नहीं किया, बल्कि वास्तव में समझा है।

प्रदर्शनी में केदारनाथ, अयोध्या राम मंदिर, कच्छ का टेंट सिटी, महाकुंभ, इंडियन आर्मी, "वंदे मातरम् – 150 वर्ष" और पारंपरिक मेलों पर आधारित 3D मॉडल्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन मॉडलों ने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कहीं श्रद्धा और आस्था की झलक थी, तो कहीं देश की सैन्य शक्ति और एकता का संदेश। इन प्रस्तुतियों ने यह साबित कर दिया कि बच्चे केवल तकनीकी ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को भी गहराई से समझ रहे हैं।

प्रदर्शनी को और अधिक रोचक बनाने के लिए अभिभावकों और अतिथियों की सहभागिता वाली गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। टंग ट्विस्टर्स, पहेलियाँ और चुनाव बूथ जैसी शैक्षणिक गतिविधियों ने सभी का ध्यान खींचा। इन गतिविधियों में बच्चों ने स्वयं मार्गदर्शन किया, जिससे उनमें नेतृत्व, संवाद और सामाजिक जागरूकता के गुण विकसित होते नजर आए। अभिभावकों ने भी बच्चों के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे विद्यालय और परिवार के बीच का जुड़ाव और मजबूत हुआ।

दिनभर चले इस आयोजन में विद्यालय परिसर सीखने की प्रयोगशाला जैसा प्रतीत हो रहा था। हर स्टॉल पर बच्चों की मेहनत, शिक्षकों का मार्गदर्शन और विद्यालय की शैक्षणिक सोच स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित होती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि "प्रोजेक्ट्स वंडरलैंड & आर्ट फिएस्टा" केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि अनुभवात्मक शिक्षा का उत्सव था। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि बच्चों को सही मंच और मार्गदर्शन मिले, तो वे अपनी सोच और प्रतिभा से समाज को नई दिशा दे सकते हैं। दीप दर्शन विद्या संकुल का यह प्रयास न केवल विद्यार्थियों के लिए यादगार रहा, बल्कि शैक्षणिक जगत के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया।

दुबई से गिरफ्तारी, मॉस्को हमला और शांति वार्ता के बीच बढ़ता रूस-यूक्रेन तनाव

जीएनएस)। मॉस्को। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले एक शीर्ष सैन्य अधिकारी पर हुए हमले के आरोपी की दुबई से गिरफ्तारी ने इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। रूस का दावा है कि रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी जीआरयू के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर गोलीबारी करने वाला मुख्य शूटर रूसी नागरिक निकला, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से गिरफ्तार कर रूस लाया गया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ताओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें और आशंकाएं दोनों ही चरम पर हैं।

शुक्रवार को मॉस्को के उत्तर-पश्चिमी इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर उस समय सनसनी फैल गई, जब लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव पर अचानक कई राउंड गोलियां चलाई गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और शूटर ने बेहद नजदीक से फायरिंग की। हमले में 64 वर्षीय अलेक्सेयेव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत एक उच्च सुरक्षा वाले सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर है, हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं माना जा रहा।

इस हमले के कुछ ही घंटों बाद रूस की

संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने दावा किया कि उसने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है। एफएसबी के अनुसार, आरोपी का नाम ल्युबोमिर कोरबा है, जो रूसी नागरिक है और हमले के बाद देश छोड़कर दुबई भाग गया था। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत दुबई की सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए उसे रूस लाया गया। रूसी एजेंसियों का कहना है कि यह केवल एक अकेले व्यक्ति की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साजिश थी, जिसमें कम से कम दो अन्य लोग भी शामिल थे। इनमें से एक को मॉस्को से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा कथित रूप से यूक्रेन भाग गया है।

रूस ने इस हमले को केवल एक आपराधिक घटना मानने से इनकार करते हुए इसे सीधे तौर पर "आतंकी हमला" करार दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमला यूक्रेन की ओर से प्रायोजित आतंकवादी कार्रवाई हो सकती है, जिसका मकसद रूस-यूक्रेन के बीच चल रही शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। लावरोव ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन अपने पश्चिमी समर्थकों के साथ मिलकर रूस के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि, यूक्रेन की सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना देता है इसका समय। हमले से ठीक एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिनों तक शांति वार्ता हुई थी। इन वार्ताओं में युद्धविराम, मानवीय गलियारों और कैदियों की अदला-बदली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जीआरयू प्रमुख एडमिरल इगोर कोस्त्युकॉव कर रहे थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्सेयेव के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में हमले को शांति प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव रूस की सैन्य और खुफिया व्यवस्था में एक बेहद प्रभावशाली नाम माने जाते हैं। वर्ष 2011 से वह जीआरयू के पहले डिप्टी चीफ के रूप में कार्यरत हैं और रूस की कई अहम सैन्य रणनीतियों में उनकी भूमिका रही है। सीरिया में रूस के सैन्य अभियान के दौरान उनकी रणनीतिक योजना और संचालन के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान 'हीरो ऑफ रूस' दिया गया था। जून 2023 में भी वह अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे, जब वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह के दौरान उन्होंने उनसे बातचीत की थी। उस समय प्रिगोजिन के लड़ाकों ने रोस्तोव-ऑन-डॉन में सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे।

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के भीतर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हमलों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। दिसंबर 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोव की कार को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके कुछ महीनों बाद अप्रैल में लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 2024 में परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरीलोव की बम धमाके में मौत ने भी रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। रूस इन सभी घटनाओं के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि यूक्रेन ने कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका स्वीकार की है और कुछ में चुप्पी साधे रखी है।

संग्रहालय से रोजगार सृजन तक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बैठक के निर्णय

जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भूमिका केवल एक तीर्थ प्रबंधन संस्था तक सीमित नहीं रही है, बल्कि समय के साथ यह बोर्ड क्षेत्रीय विकास, स्थानीय रोजगार और सामाजिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम बनता गया है। 8 फरवरी को जम्मू के लोक भवन में आयोजित श्राइन बोर्ड की बैठक ने इसी व्यापक सोच को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में ऐसे कई निर्णय लिए गए, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में केवल माता वैष्णो देवी धाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कटरा, रियासी, जम्मू और आसपास के क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर भी गहराई से पड़ेगा।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा के साथ-साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर समान रूप से जोर दिया गया। बोर्ड ने माना कि तीर्थ स्थल की गरिमा और व्यवस्थाओं का सीधा संबंध वहां रहने वाले लोगों की आजीविका, शिक्षा और रोजगार से है। इसी सोच के तहत मां शक्ति की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह संग्रहालय केवल एक इमारत या प्रदर्शनी स्थल नहीं होगा, बल्कि इसमें माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा, शाक्त परंपरा, भारतीय दर्शन और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ-साथ ज्ञान और अनुभव का एक नया आयाम मिलेगा।

इसके साथ ही साउंड एंड लाइट शो और एक विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार करने का

फैसला भी लिया गया, जिससे तीर्थ यात्रियों को माता के इतिहास, मान्यताओं और परंपराओं को रोचक और भावनात्मक रूप में समझने का अवसर मिलेगा। विश्व के कई प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर इस तरह के शो लोगों को आकर्षित करते हैं और लंबे समय तक उनकी स्मृति में बसे रहते हैं। वैष्णो देवी धाम में इस पहल से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए तकनीकी, रचनात्मक और प्रबंधन से जुड़े नए अवसर भी पैदा होंगे।

बैठक में यह भी महसूस किया गया कि किसी भी बड़े धार्मिक स्थल की सफलता का असली आधार वहां की सुचारु व्यवस्थाएं और प्रशिक्षित मानव संसाधन होते हैं। इसी कारण श्राइन बोर्ड ने अपने यहां लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने का निर्णय लिया। यह कदम स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका का अवसर मिलेगा। रोजगार सृजन की यह नीति केवल स्थायी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अप्रत्यक्ष रूप से सेवाओं, परिवहन, होटल, खानपान और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी अवसर बढ़ेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बोर्ड ने एक दूरगामी सोच का परिचय दिया। बैठक में आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए मुफ्त नीट कोचिंग केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें।

भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत में सपनों को मिली उड़ान, 3640 विद्यार्थियों ने थामी नई जिम्मेदारियों की राह

जीएनएस)। सूरत। शिक्षा के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त रूप देने वाला क्षण उस समय देखने को मिला, जब भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, वेसु का पाँचवां दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। रविवार, 8 फरवरी 2026 को शाम 4:30 बजे आयोजित इस समारोह में हजारों विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, लगन और सपनों को औपचारिक पहचान मिली। यूनिवर्सिटी परिसर उत्साह, गर्व और भावनाओं से भरा हुआ नजर आया, जहां विद्यार्थियों के चेहरों पर सफलता की मुस्कान और अभिभावकों की आंखों में संतोष साफ झलक रहा था।

इस भव्य अवसर पर रेल मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्री विजय शर्मा तथा भारत की पूर्व विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों की मौजूदगी ने समारोह को न केवल विशेष बनाया, बल्कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत भी बनी। दीक्षांत समारोह में

विश्वविद्यालय के 17 कॉलेजों से जुड़े कुल 3640 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध की विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गईं। जब एक-एक कर विद्यार्थी मंच पर पहुंचे और उन्हें डिग्री प्रदान की गई, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

इस अवसर पर विज्ञान, फार्मेसी, शिक्षा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और रिसर्च सहित अनेक संकायों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बीएससी, बी.फार्मेसी, बी.एड, एम.एड, बीसीए, बीबीए, बीपीएड, एमबीए, एमसीए, एमपीएड और नर्सिंग जैसी विभिन्न स्ट्रीम के विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी डिग्रियां प्राप्त कीं। इसके साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 48 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 48 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल प्रदान किए गए, जबकि 24 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह पल उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से भावुक था, जिन्होंने वर्षों तक शोध और अध्ययन में खुद को समर्पित किया।

भगवान महावीर एजुकेशन फाउंडेशन के डॉ. संजय जैन और मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अनिल जैन ने इसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अल्प समय में शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 17 विभिन्न फैकल्टी के अंतर्गत आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फार्मेसी, आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समारोह की शुरुआत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्पीच के माध्यम से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी शिक्षा के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक दायित्व को भी समान महत्व दे रही है।

अपने प्रेरक संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में केवल प्रथम आना ही सफलता का पैमाना नहीं होता, बल्कि असली सफलता यह है कि व्यक्ति काबिल, जिम्मेदार और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने। उन्होंने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि आज मिली डिग्री केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। समाज, राज्य और देश के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए आगे बढ़ना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है।

मुख्य अतिथि श्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्राप्त की गई डिग्री केवल एक प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का द्वार है। उन्होंने विद्यार्थियों को ईमानदारी, अनुशासन और कड़ी मेहनत को जीवन का मूल मंत्र बनाने की सलाह दी। उनका कहना था कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और आज के विद्यार्थी ही कल के नेतृत्वकर्ता हैं।

दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले। कई अभिभावकों की आंखों में गर्व के आंसू थे, तो कई विद्यार्थियों के लिए यह पल अपने संघर्ष और सपनों की परिणति जैसा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, गरिमा और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला।

पुनागांव के निधि टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, काले धुएं ने दहला दिया इलाका

जीएनएस)। सूरत। सूरत के पुनागांव क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब निधि टेक्सटाइल मार्केट के पहले बेसमेंट से अचानक आग की लपटें और घना काला धुआं उठने लगा। सुबह के शांत माहौल में अचानक फैले धुएं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में धुआं इतनी तेजी से फैला कि वह पांचवीं मंजिल तक पहुंच गया, जिससे बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी इमारत आग की चपेट में आ चुकी हो।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग बेसमेंट में लगी, जहां बिजली की वायरिंग के साथ-साथ बड़ी मात्रा में लकड़ी का सामान रखा हुआ था। इन्हीं ज्वलनशील वस्तुओं के कारण आग ने बहुत कम समय में विकराल रूप धारण कर लिया। बेसमेंट से उठे घने काले धुएं ने पूरे मार्केट परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग घबराकर सड़क पर निकल आए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

घटना की जानकारी मिलते ही सूरत फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई। शुरुआत में शहर के पांच अलग-अलग फायर स्टेशनों से 10 फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए, लेकिन आग की भयावहता और धुएं की तीव्रता को देखते हुए चीफ फायर ऑफिसर ने तुरंत 'ब्रिगेड कॉल' जारी कर दिया। इसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों से अतिरिक्त फायर टेंडर मंगवाए गए और कुल 20 से 25 फायर इंजन घटनास्थल पर तैनात किए गए।

आग बुझाने का काम आसान नहीं था। बेसमेंट में फैले घने धुएं के कारण दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी। फायरमैन को ऑक्सीजन मास्क पहनकर बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करना पड़ा। अंदर का दृश्य बेहद चुनौतीपूर्ण था, जहां चारों ओर धुआं ही धुआं था और आग के स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड के जवानों ने साहस और सूझबूझ के साथ करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास किए और आखिरकार आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। इसके बाद लंबे समय तक कूलिंग की प्रक्रिया चलाई गई, ताकि दोबारा आग भड़कने की कोई संभावना न रहे।

रविवार का दिन होने के कारण टेक्सटाइल मार्केट पूरी तरह बंद था। इसी वजह से किसी व्यापारी या कर्मचारी के अंदर फंसे होने की आशंका नहीं रही और किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। यह एक बड़ी राहत की बात रही, क्योंकि यदि यह घटना किसी कार्यदिवस में होती, तो जान-माल के नुकसान की आशंका काफी अधिक हो सकती थी। हालांकि आग से बेसमेंट में रखे बिजली के उपकरण, वायरिंग और अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। डिविजनल फायर ऑफिसर कृष्णा मोध ने बताया कि बेसमेंट में लगी वायरिंग प्लेट में आग लगने के बाद वह तेजी से बिजली के मीटर बॉक्स तक फैल गई। वहां मौजूद लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण धुआं तेजी से फैला, जिससे पूरी इमारत में आग फैलने का भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इमारत में फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक उपकरण मौजूद थे और जांच के दौरान वे चालू हालत में पाए गए।

घटना के बाद कुछ समय तक आसपास के इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। आग पर काबू पाने के बाद जब धुआं धीरे-धीरे छंटा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।